

Daily Current Affairs

Date : 23 May, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	पोखरण में 'वायु अस्त्र-1' का सफल परीक्षण
2.	राजस्थान मंत्रिमण्डल की बैठक (22 मई, 2026)
3.	राजस्थान में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन
4.	राजस्थान में 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM- UShA)' की स्थिति
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. कर्पूर चन्द्र कुलिश शोध संस्थान 2. राजस्थान का प्रथम ग्रामीण 3R सेंटर 'शक्ति संगम' 3. राजस्थान का पहला ड्यूल-सोर्स पावर सप्लाई वाला डेटा सेंटर : जयपुर 4. चैन सिंह राठौड़ : RSGA के नए अध्यक्ष 5. राजस्थान में ग्रीन एनर्जी क्षेत्र का सबसे बड़ा विदेशी निवेश 6. कीड़ीनगरा की दवा का क्लीनिकल ट्रायल : जोधपुर 7. राज्य की पहली हरिजन पाठशाला के 100 वर्ष पूर्ण 8. राजस्थान में साइबर ठगी के नवीनतम आँकड़े
6.	मेजर अभिलाषा बराक
7.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस: पहला महिला पर्वतारोहण अभियान
8.	एकीकृत लॉजिस्टिक एप्लिकेशन: 'क्यू-फोर्स'
9.	'द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया: द स्टोरी ऑफ पी. एन. पणिकर' पुस्तक
10.	श्रीयांशी वलीशेट्टी
11.	साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स की भारत यात्रा
12.	रूस और चीन के बीच प्रगाढ़ होते संबंध
13.	भारत की सांस्कृतिक कूटनीति
14.	एशियाई उत्पादकता संगठन (APO)
15.	स्मॉल हाइड्रो स्कीम (लघु जल विद्युत विकास योजना)
16.	अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2026
17.	निकट दृष्टि दोष (मायोपिया)
18.	बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-1'

--:1:--

राजस्थान परिदृश्य

पोखरण में 'वायु अस्त्र-1' का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी लोडिंग म्यूनिशन सिस्टम 'वायु अस्त्र-1' का सफल परीक्षण किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- परीक्षणकर्ता** : पुणे की रक्षा कंपनी नाइब लिमिटेड (Nibe Limited) द्वारा।
- यह परीक्षण 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत सेना की मारक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- मारक क्षमता** : इस आधुनिक सुसाइड ड्रोन की मारक क्षमता 100 किलोमीटर है।
- सटीकता (High Precision)** : परीक्षण में इस प्रणाली ने 1 मीटर से भी कम का 'सर्कुलर एरर प्रोबेबल' (CEP) हासिल किया।

--2--

Daily Current Affairs

Date : 23 May, 2026



- **वॉरहेड** : यह ड्रोन 10 किलोग्राम के विस्फोटक से लैस है।
- **उन्नत नियंत्रण प्रणाली** : युद्धक्षेत्र में लचीलापन बढ़ाने के लिए इसका नियंत्रण ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (GCS) से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित फॉरवर्ड कंट्रोल स्टेशन (FCS) को सफलतापूर्वक ट्रांसफर किया गया।
- **हमला रोकने और दोबारा हमले की क्षमता (Abort & Re-attack)** : यह ड्रोन मिशन को बीच में ही रद्द करने (Abort) और फिर से नया लक्ष्य निर्धारित कर दोबारा हमला करने (Re-attack) की विशिष्ट तकनीक से लैस है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--3--

राजस्थान मंत्रिमण्डल की बैठक (22 मई, 2026)



चर्चा में क्यों?

- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 22 मई, 2026 को राजस्थान मंत्रिमण्डल की बैठक सम्पन्न हुई।



The infographic features the Government of Rajasthan logo and the text 'राजस्थान सरकार GOVERNMENT OF RAJASTHAN'. The main title is 'कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय' (Cabinet's Important Decision) dated '22 मई 2026'. A circular inset shows a man in a yellow shirt speaking. The central theme is '4G' (Green, Governance, Growth, Globalization). The policy is titled 'राजस्थान इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन' (Approval of Rajasthan Industrial Development Policy). The policy aims to establish the state as a global industrial hub. It is based on the 4G policy and was approved on May 22, 2026. The policy's goal is to achieve an industrial development of 350 billion dollars by 2028-29.

राजस्थान इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन

- प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने हेतु मंत्रिमंडल ने 4G - Green, Governance, Growth एवं Globalization आधारित राजस्थान इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है
- इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए वर्ष 2028-29 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है

f BhajanlalBJP | @bjpbhajanlal | X BhajanlalBjp | • cmbhajanlal

--:4:--



मुख्य बिन्दु:

राजस्थान इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन:

- अनुमोदन : मंत्रिमण्डल की बैठक में 22 मई, 2026 को।
- संबंधित विभाग : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (राजस्थान)
- नीति के चार रणनीतिक स्तंभ : 4G - ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन।
- नीति का मुख्य लक्ष्य : राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028-29 तक \$350 बिलियन तक पहुँचाना।

मुख्य प्रावधान :

- इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन, अक्षय ऊर्जा तथा सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- नीति के माध्यम से रीको एवं नॉन-रीको क्षेत्रों में CETP (Common Effluent Treatment Plant) की स्थापना के लिए नई योजनाएँ लाई जायेंगी तथा नए इंट्रीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्कों की स्थापना की जायेगी।
- DMIC (दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर) में नोड आधारित औद्योगिक पार्कों के विकास का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- फास्ट ट्रेक अप्रूवल्स, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, CETP एवं प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
- साथ ही, नवीन तकनीकों पर आधारित उद्योग; जैसे - सेमीकण्डक्टर, डाटा सेंटर, जी.सी.सी. एवं डिफेंस मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ जैम्स एंड ज्वैलरी, टैक्सटाइल, टूरिज्म, हैण्डीक्राफ्ट, एग्रो प्रोसेसिंग, डेयरी तथा लॉजिस्टिक्स इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।
- यह नीति रिसर्च एण्ड डवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर केन्द्रित है, जिससे प्रदेश में निवेश और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन:

- राजस्थान मंत्रिमण्डल द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में तीन संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई।
- **संशोधित नियम - 67** : विशेष योग्यजनों को स्थाई विकलांगता का प्रमाण-पत्र एक बार ही प्रस्तुत करना होगा। पहले इस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता प्रति तीन वर्ष नियत थी।
- **संशोधित नियम - 134** : पेंशनर्स को मोबाइल ऐप द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही, राजपत्रित अधिकारियों के साथ अराजपत्रित कार्मिकों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) को भी SSO आईडी से जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु अधिकृत किया गया है।
- **प्रपत्र-14 में संशोधन** : दो राजपत्रित अधिकारियों अथवा सम्मानित व्यक्तियों द्वारा परिवार पेंशन के लिए प्रमाणीकरण किया जाता था। अब दो के स्थान पर केवल एक राजपत्रित अधिकारी या सम्मानित व्यक्ति का प्रमाणीकरण ही पर्याप्त होगा।

जैसलमेर में सीमेंट संयंत्र (क्लिंगराइजेशन यूनिट) के लिए भूमि का आवंटन :

- राजस्थान मंत्रिमण्डल द्वारा मैसर्स डालमिया सीमेंट को जैसलमेर में 121.42 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 के अंतर्गत प्रदान की गई।
- डालमिया सीमेंट कम्पनी द्वारा इस स्थान पर 3.6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला सीमेंट संयंत्र (क्लिंगराइजेशन यूनिट) स्थापित किया जाएगा।

अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन

- **जैसलमेर** - मगरा, बासड़ा और घोटासू ग्राम।
- **बाड़मेर** - मुंगेरिया ग्राम।
- **बीकानेर** - करणीसर भाटियान एवं बरजू ग्राम ।

राजस्थान में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा राजस्थान को विभिन्न रेल सेवाओं और परियोजनाओं की सौगात दी गई।



मुख्य बिन्दु:

- जैसलमेर में ₹67 करोड़ की लागत से निर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया।
- जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस की डिब्बा संरचना को 8 कोच से बढ़ाकर 20 कोच किया गया।
- साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस रेल सेवा का जैसलमेर तक विस्तार किया गया।
- जालौर-दिल्ली उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा का शुभारंभ।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- राजस्थान में 25 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 12 पूर्ण हो चुके हैं।
- केंद्र सरकार की 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत राजस्थान में 85 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प और पुनर्विकास किया जा रहा है।
- भगत की कोठी (जोधपुर) में वंदे भारत स्लीपर टर्मिनल विकसित किया जा रहा है।

--7--

राजस्थान में 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM- UShA)' की स्थिति

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान में 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-UShA)' के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 4 राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों एवं 30 राजकीय महाविद्यालयों की 34 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लागत ₹330 करोड़ है।



प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-UShA)

मुख्य बिन्दु:

- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM- UShA) के अंतर्गत जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर सबसे पहले चयनित होने वाला विश्वविद्यालय था।

इस अभियान के अंतर्गत राजस्थान के चयनित विश्वविद्यालय:

- गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बाँसवाड़ा।
- महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
- जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- मुगनीराम बांगड़ मेमोरियल यूनिवर्सिटी, जोधपुर।

--:8:--

Daily Current Affairs

Date : 23 May, 2026



- **नोट :** राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) 1.0 एवं 2.0 के तहत राजस्थान में 5 विश्वविद्यालयों एवं 116 महाविद्यालयों में कुल 130 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लागत ₹611 करोड़ है।

RUSA के अंतर्गत राजस्थान के चयनित विश्वविद्यालय:

- मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
- जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
- कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- वर्ष 2013 और 2018 में शुरू क्रमशः 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) - 1.0 और 2.0 केंद्र प्रायोजित अभियान थे।
- इन अभियानों को जून, 2023 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) - 2020 के तहत पुनर्गठित कर 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM- UShA)' के रूप में शुरू किया गया।
- PM- UShA अभियान के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान शामिल हैं।

--9--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>कर्पूर चन्द्र कुलिश शोध संस्थान</p> <ul style="list-style-type: none">उदयपुर स्थित जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के प्रतापनगर परिसर में 'कर्पूर चन्द्र कुलिश शोध संस्थान' की स्थापना की गई है।यह संस्थान राजस्थान पत्रिका के संस्थापक और हिंदी पत्रकारिता के पुरोधा कर्पूर चन्द्र कुलिश की स्मृति और उनके वैचारिक योगदान को समर्पित है।
2.	<p>राजस्थान का प्रथम ग्रामीण 3R सेंटर 'शक्ति संगम'</p> <ul style="list-style-type: none">राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान का प्रथम ग्रामीण 3R (Reduce, Reuse, Recycle) सेंटर 'शक्ति संगम' जयपुर जिले की खेजड़ावास पंचायत में स्थापित किया गया है।उद्देश्य : 'वेस्ट टू आर्ट' की संकल्पना के तहत घरों से निकलने वाले अनुपयोगी सामान; जैसे - पुराने कपड़े, टायर, पंखे, खिलौने और किताबें आदि को रिसाईकल कर नया रूप देना है।
3.	<p>राजस्थान का पहला ड्यूल-सोर्स पावर सप्लाय वाला डेटा सेंटर : जयपुर</p> <ul style="list-style-type: none">जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में STT ग्लोबल डेटा सेंटर में राजस्थान का पहला ड्यूल-सोर्स पावर सप्लाय वाला डेटा सेंटर स्थापित किया गया है।इस तकनीकी व्यवस्था से डेटा सेंटर को मिलने वाली बिजली की निर्भरता किसी एक ग्रिड पर नहीं रहेगी, जिससे बिना किसी रुकावट के निर्बाध डिजिटल सेवाएँ सुनिश्चित होंगी।
4.	<p>चैन सिंह राठौड़ : RSGA के नए अध्यक्ष</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, कोटा में संपन्न हुए चुनावों में चैन सिंह राठौड़ को लगातार तीसरी बार राजस्थान राज्य जिम्नास्टिक्स संघ (RSGA) का अध्यक्ष चुना गया।यह चुनाव वर्ष 2026 से 2030 तक के 4 साल के कार्यकाल के लिए आयोजित किए गए थे।

5.	<p>राजस्थान में ग्रीन एनर्जी क्षेत्र का सबसे बड़ा विदेशी निवेश</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान में ग्रीन एनर्जी क्षेत्र का सबसे बड़ा विदेशी निवेश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा किया जा रहा है।■ UAE अपने सरकारी फंड से करीब ₹3 लाख करोड़ का निवेश राजस्थान में करेगी। इसके तहत जैसलमेर के घोटारू क्षेत्र में 60 गीगावाट क्षमता का देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब स्थापित होगा। इसमें सोलर, विंड और हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट शामिल हैं।■ इस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार और UAE सरकार के मध्य 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के दौरान समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
6.	<p>कीड़ीनगरा की दवा का क्लीनिकल ट्रायल : जोधपुर</p> <ul style="list-style-type: none">■ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से संबद्ध संस्था DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative) द्वारा कीड़ीनगरा (Eumycetoma) बीमारी की दवा का अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्लीनिकल ट्रायल डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में किया जाएगा।■ इस बहु-देशीय अंतरराष्ट्रीय परीक्षण का उद्देश्य कवक (Fungus) से होने वाले माइसेटोमा/ कीड़ीनगरा (Eumycetoma) के मरीजों के लिए सुरक्षित, सस्ती और प्रभावी दवा उपलब्ध कराना है।
7.	<p>राज्य की पहली हरिजन पाठशाला के 100 वर्ष पूर्ण</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान चरखा संघ के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से जयपुर के अमरसर में वर्ष 1926 में राज्य की पहली हरिजन पाठशाला स्थापित की गई थी।■ वर्ष 2026 में यह पाठशाला अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर रही है।
8.	<p>राजस्थान में साइबर ठगी के नवीनतम आँकड़े</p> <ul style="list-style-type: none">■ केंद्र सरकार के 'प्रतिबिम्ब पोर्टल' के ताजा आँकड़ों के अनुसार राजस्थान के 4 जिले देश के सबसे सक्रिय साइबर फ्रॉड जिलों में शामिल हैं।■ अलवर : देश में चौथा स्थान।■ खैरथल-तिजारा : देश में 10वाँ स्थान।■ डीग : देश में 11वाँ स्थान।■ जयपुर : देश में 16वाँ स्थान।



राष्ट्रीय परिदृश्य



मेजर अभिलाषा बराक

(स्रोत: PIB और DD-NEWS)



चर्चा में क्यों?

- लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार (वर्ष 2016 में स्थापित) के लिए चुना गया है।



मुख्य बिन्दु:

- मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं।
- मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं।
- मेजर बराक यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांतिरक्षक बन गई हैं। इससे पूर्व मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 में और मेजर राधिका सेन को वर्ष 2023 में यह पुरस्कार मिला था।
- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में से एक है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

- शिशुपाल सिंह, सांवला राम विश्रोई तथा शबर ताहिर अली:** वर्ष 2023 में, भारत को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च शांति सम्मान, डाग हैमरशॉल्ड पदक मिला, जो भारतीय शांति सैनिकों शिशुपाल सिंह और सांवला राम विश्रोई और नागरिक संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ता शबर ताहिर अली को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में उनके बलिदान के लिए मरणोपरांत प्रदान किया गया।

--:12:--

- **भारत का योगदान:** 1950 के दशक से, भारत ने विश्व भर में 50 से अधिक मिशनों में 290,000 से अधिक शांति सैनिकों को भेजा है, जिससे यह संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयासों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। वर्तमान में, 5,000 से अधिक भारतीय सैनिक ग्यारह सक्रिय मिशनों में से नौ में सेवारत हैं।
- वैश्विक प्रयासों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र के 70,000 वर्दीधारी शांति सैनिकों में से अभी भी महिलाओं की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है, जिसमें सैन्य कर्मी, पुलिस अधिकारी और पर्यवेक्षक शामिल हैं।
- अधिक लैंगिक समावेशिता की आवश्यकता हेतु संयुक्त राष्ट्र ने अपनी समान लैंगिक समानता रणनीति के तहत वर्ष 2028 तक सैन्य टुकड़ियों में 15 प्रतिशत और पुलिस इकाइयों में 25 प्रतिशत महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।



भारत-तिब्बत सीमा पुलिस: पहला महिला पर्वतारोहण अभियान

(स्रोत: DD-NEWS)

चर्चा में क्यों?

- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने एवरेस्ट शिखर पर पहला महिला पर्वतारोहण अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।



मुख्य बिन्दु:

- **दल:** 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और तीन तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे।
- स्वच्छ हिमालय-ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत, दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियाँ भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया।
- इस उपलब्धि के साथ, दल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर पांच सफल चढ़ाई शामिल हैं। दल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ल्होत्से, धौलागिरि और मनास्लू सहित विश्व की 8 हजार मीटर से अधिक ऊँची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की हैं।

एकीकृत लॉजिस्टिक एप्लिकेशन: 'क्यू-फोर्स'

(स्रोत: AIR)

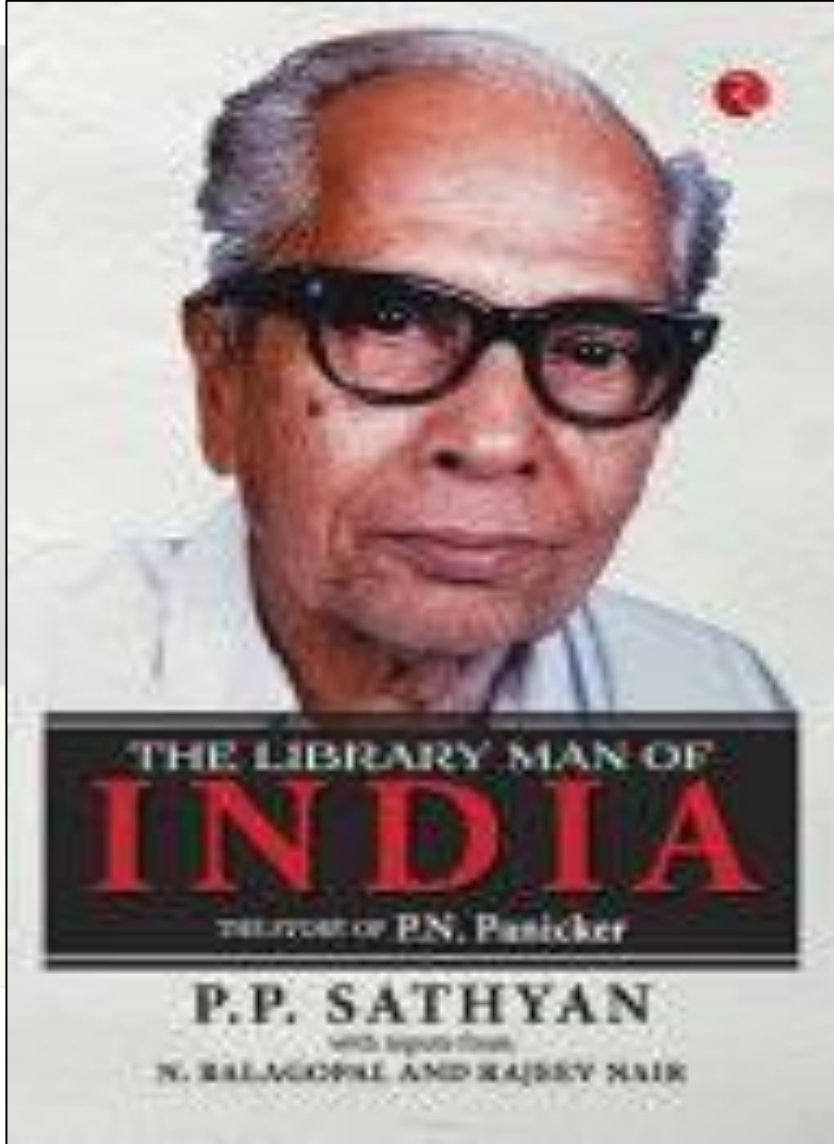


मुख्य बिन्दु:

- भारतीय सेना ने रसद और आपूर्ति प्रबंधन सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत एप्लिकेशन 'क्यू-फोर्स' का शुभारंभ किया है।
- यह एप्लिकेशन कई लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री प्लेटफॉर्म को एकीकृत कर आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन प्रबंधन को मजबूत करेगा। इससे विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में कार्य में तेजी आयेगी।

'द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया: द स्टोरी ऑफ पी. एन. पणिककर'
पुस्तक

(स्रोत: PIB और DD-NEWS)



मुख्य बिन्दु:

- भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में पी. पी. सत्यन द्वारा लिखित पुस्तक 'द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया: द स्टोरी ऑफ पी. एन. पणिककर' का विमोचन किया।

--:16:--

श्रीयांशी वलीशेट्टी

(स्रोत: AIR)



मुख्य बिन्दु:

- बैडमिंटन में 17 मई, 2026 को भारत की श्रीयांशी वलीशेट्टी ने चीन में आयोजित बाओजी चाइना मास्टर्स में महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता।
- बाओजी सिटी जिम्नेजियम में खेले गए सुपर 100 स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में उन्हें स्थानीय खिलाड़ी आन क्यू युआन ने सीधे सेटों में 14-21, 6-21 से हरा दिया।

--:17:--

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स की भारत यात्रा

(स्रोत: PIB, AIR और विदेश मंत्रालय)

चर्चा में क्यों?

- 20 से 23 मई, 2026 को साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स की भारत की राजकीय यात्रा सम्पन्न की।



मुख्य बिन्दु:

- राष्ट्रपति पद पर रहते हुए क्रिस्टोडौलाइड्स का यह पहला भारत दौरा है।
- दोनों देश फरवरी, 2027 में राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूर्ण करेंगे।

--:18:--

परिणाम:

समझौता ज्ञापन

1. आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की स्थापना पर समझौता ज्ञापन
2. सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान एवं साइप्रस राजनयिक अकादमी के बीच समझौता
3. नवाचार और प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन
4. साइप्रस के लारनाका संयुक्त बचाव समन्वय केंद्र और भारत के रक्षा मंत्रालय के बीच खोज एवं बचाव (एसएआर) मामलों तकनीकी व्यवस्था हेतु समझौता
5. उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन
6. सांस्कृतिक सहयोग (2026-2030) पर समझौता ज्ञापन

घोषणाएँ:

शीर्षक

- भारत और साइप्रस के बीच 2026-2031 की अवधि के लिए रक्षा सहयोग का रोडमैप
- भारत और साइप्रस के बीच साइबर सुरक्षा संवाद की स्थापना
- भारत और साइप्रस के बीच वाणिज्य दूतावास (कांसुलर) संवाद की स्थापना
- साइप्रस "व्यापार, संपर्क और समुद्री परिवहन" स्तंभ के तहत हिंद-प्रशांत महासागर पहल में शामिल हो रहा है।
- सहयोग हित और मैत्री (BHISM) क्यूब के लिए भारत स्वास्थ्य पहल का साइप्रस को उपहार स्वरूप दिया जाना।
- 18 मई, 2026 को पहले भारत-साइप्रस अंतरिक्ष दिवस का आयोजन।
- साइप्रस की ओर से मुंबई में साइप्रस व्यापार केंद्र खोलने के आशय की घोषणा।
- भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में निवेश प्रवाह को फिर से दोगुना करना है।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

रूस और चीन के बीच प्रगाढ़ होते संबंध

(Source: Indian express)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में रूसी राष्ट्रपति की चीन यात्रा ने रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता को रेखांकित किया। दोनों पक्षों ने 40 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के खिलाफ एक 'बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था' के लिए अपने समर्थन को दोहराया।



मुख्य बिन्दु:

रूस-चीन के प्रगाढ़ होते संबंधों के कारण

- साझा भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था को अपने मूल हितों के लिए खतरा मानते हैं।

--:20:--

Daily Current Affairs

Date : 23 May, 2026



- **आर्थिक पूरक की भूमिका:** पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ा दी है।
- **डी-डॉलराइजेशन और वैकल्पिक संस्थाएँ:** चीन की युआन मुद्रा और रूस की रूबल मुद्रा में व्यापार लगातार बढ़ रहा है। साथ ही, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों का उपयोग गैर-पश्चिमी यूरेशियाई सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।

भारत पर प्रभाव

- **रणनीतिक संतुलनकर्ता के रूप में रूस की भूमिका में कमी:** रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता भारत-चीन तनावों में उसकी तटस्थता को कमजोर कर रही है।
- **रक्षा संबंधी कमजोरियाँ:** भारत की रूसी हथियारों (जैसे कि S-400 व स्टेल्थ फ्रिगेट्स) पर निर्भरता आपूर्ति में देरी के संकट का सामना कर रही है। साथ ही, रूस द्वारा चीन को अत्याधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्मों की बिक्री से भारत की सुरक्षा चिंताएँ बढ़ी हैं।
- **रूस-चीन-पाकिस्तान के उभरते संबंध:** रूस हथियारों की बिक्री और रियायती तेल निर्यात के माध्यम से पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सुदृढ़ कर रहा है।
- **बहुपक्षीय मंचों पर चुनौतियाँ:** शंघाई सहयोग संगठन में रूस और चीन के बीच सहयोग बढ़ रहा है।
- **भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर दबाव:** रूस-चीन की बढ़ती नजदीकी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अनिश्चित नीतियाँ भारत की बहु-पक्षीय मंचों के साथ जुड़ने की रणनीति को सीमित कर रही हैं।

-:21:-

भारत की सांस्कृतिक कूटनीति

(Source: Indian express)

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और इटली की अपनी पाँच देशों की राजनयिक यात्रा के दौरान विश्व नेताओं को पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, वस्त्र और क्षेत्रीय कलाकृतियाँ भेंट कीं।



मुख्य बिन्दु:

विश्व नेताओं को भेंट किए गए उपहार

- इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को असम से मूगा रेशम का शॉल और मणिपुर से ऑफ-व्हाइट रंग का शिरुई लिली रेशम का शॉल भेंट किया गया।
- मुगा रेशम, जिसे असम का "सुनहरा रेशम" कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना कृत्रिम रंगों के उत्पादित एक दुर्लभ वस्त्र है।

--:22:--

- शिरुई लिली सिल्क स्टोल मणिपुर के शिरुई काशोंग शिखर और दुर्लभ शिरुई लिली फूल से प्रेरित है।
- नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा को राजस्थान से मीनाकारी और कुंदन की बालियां उपहार में मिली थीं।
- नॉर्वे के नेता जोनास गहर स्टोरे को सिक्किम के असली सूखे ऑर्किड और फर्न से बनी एक सूखी ऑर्किड की पेंटिंग और ऑर्किड पेपरवेट भेंट किए गए।
- हेराल्ड पंचम को ओडिशा के कटक की पारंपरिक चाँदी की नक्काशी कला, तारकासी का उपयोग करके तैयार की गई चाँदी की नाव का एक मॉडल भेंट किया गया।
- स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन को पश्चिम बंगाल से रवींद्रनाथ टैगोर की कृतियों के साथ एक शांतिनिकेतन संदेशवाहक बैग प्राप्त हुआ।
- संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को गुजरात से रोगन द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग प्राप्त हुई, जिसमें "जीवन वृक्ष" का प्रतीक चिन्ह दर्शाया गया है।
- रोगन कला गुजरात के कच्छ क्षेत्र की एक दुर्लभ वस्त्र चित्रकारी परंपरा है।
- गुजरात के जूनागढ़ से लाए गए केसर आमों का एक डिब्बा भी भेंट किया गया।

महत्त्व

- ये उपहार स्थानीय कारीगरों, पारंपरिक शिल्पकलाओं और भौगोलिक संकेत (GI) से जुड़े उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देते हैं।
- वे सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करते हैं और वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं।

एशियाई उत्पादकता संगठन (APO)

(Source: PIB)

चर्चा में क्यों?

- भारत ने क्षेत्रीय उत्पादकता सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय की 68वीं बैठक की मेजबानी की।



Asian Productivity Organisation

मुख्य बिन्दु:

एशियाई उत्पादकता संगठन

- 1961 में स्थापित, यह टोक्यो स्थित एक अंतरसरकारी निकाय है जो पारस्परिक सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देता है।
- वर्तमान में APO में बांग्लादेश, कंबोडिया, ताइवान, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया गणराज्य, लाओ पीडीआर, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम सहित 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

स्मॉल हाइड्रो स्कीम (लघु जल विद्युत विकास योजना)

(स्रोत: PIB और DD-NEWS)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकेंद्रीकृत स्वच्छ ऊर्जा को पुनर्जीवित करने और लगभग 1,500 मेगावाट क्षमता स्थापित करने के लिए 2,584 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लघु जल विद्युत (SHP) विकास योजना (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) को मंजूरी दी।

SMALL HYDRO POWER (SHP) DEVELOPMENT SCHEME



मुख्य बिन्दु:

- उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य छोटे जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और दूरदराज के इलाकों तक बिजली पहुँचाना है।
- परियोजना का दायरा:** यह योजना 1 मेगावाट और 25 मेगावाट के बीच की क्षमता वाली छोटी जलविद्युत परियोजनाओं का समर्थन करती है, जो पहाड़ी और उत्तर पूर्वी (NE) राज्यों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाले जिलों पर केंद्रित है।

--:25:--

Daily Current Affairs

Date : 23 May, 2026



- **लक्ष्य:** 2026-27 से 2030-31 के मध्य करीब 1,500 मेगावाट नई क्षमता जोड़ना।
- वर्तमान में देश में करीब 5,171 मेगावाट छोटी जल विद्युत क्षमता का उपयोग हो रहा है, जबकि कुल संभावित क्षमता 21,133 मेगावाट से अधिक है।
- **केंद्रीय वित्तीय सहायता:**
 - पूर्वोत्तर राज्यों और सीमावर्ती जिलों के लिए: 3.6 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30% (जो भी कम हो), प्रति परियोजना 30 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ।
 - अन्य राज्य: 2.4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 20% (जो भी कम हो), प्रति परियोजना अधिकतम 20 करोड़ रुपये की सीमा के साथ।
- इस योजना से लगभग 51 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:26:--

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2026

(स्रोत: PIB, CBD, DD-NEWS और AIR)

चर्चा में क्यों?

- 22 मई, 2026 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM) में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2026 के राष्ट्रीय स्तर के समारोह और चीता संरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की।



मुख्य बिन्दु:

- कार्यक्रम का विषय:** यह कार्यक्रम 'वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना' विषय पर आधारित था।

-:27:-

Daily Current Affairs

Date : 23 May, 2026



- **सहयोग:** यह कार्यक्रम केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) के सहयोग से आयोजित किया गया था।
- **इस अवसर पर निम्नलिखित प्रकाशन, पहल और प्रचार सामग्री जारी की गई:**
 1. अनुकूलित माईस्टैम्प
 2. भारत की जैव विविधता रिपोर्ट, 2026: CBD को सौंपी गई सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट से प्राप्त अंतर्दृष्टि
 3. ABS के कार्यान्वयन में भारत की प्रगति: नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट से प्राप्त अंतर्दृष्टि
 4. ABS एंड-टू-एंड पोर्टल
 5. पहुँच और लाभ साझाकरण पर फिल्म
 6. अमरकंटक जैव विविधता विरासत स्थल पर फिल्म
 7. मध्य प्रदेश के देवलोक वनों (पवित्र उपवनों) के संरक्षण पर बनी फिल्म
- **तिथि:** 22 मई
- **वर्ष 2026 का विषय/ थीम:** 'वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना' (Acting Locally for Global Impact)।
- **उद्देश्य:** जैव विविधता के महत्त्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानव जीवन, जलवायु सुरक्षा, और खाद्य सुरक्षा में इसकी भूमिका को समझना।
- **इतिहास:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on Biological Diversity- UNCBD) 22 मई, 1992 को अपनाया गया था।

--:28:--

- UNCBD जैवविविधता के संरक्षण के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है।
- भारत इस संधि का एक पक्षकार है और इसने जैवविविधता अधिनियम, 2002 लागू किया है।
- **तिथि संशोधन:** शुरुआत में यह दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन बाद में वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी तारीख बदलकर 22 मई कर दी।
- वर्ष 2026 का आयोजन 2022 में अपनाई गई कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क नामक वैश्विक योजना पर आधारित है।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा:

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा अपनाने के तहत, प्रकृति के क्षरण को रोकने और उसे पलटने के लिए वर्ष 2030 तक 23 लक्ष्य और वर्ष 2050 तक 4 वैश्विक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं;
- **उद्देश्य-1:** वर्ष 2030 तक 30% खराब हो चुके पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करना।
- **उद्देश्य-2:** 30% भूमि, जल और समुद्र का संरक्षण करना।
- **उद्देश्य-3:** आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश या बसावट को 50% तक कम करना।
- **उद्देश्य-4:** जैव विविधता के लिए प्रति वर्ष 200 अरब डॉलर जुटाना।

जैव विविधता:

- जैवविविधता शब्द एक अवधारणा के रूप में पहली बार वर्ष 1985 में वाल्टर जी. रोसेन द्वारा दिया गया, जिसमें पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों और मनुष्यों सहित सभी जीवन रूपों की विविधता शामिल हैं।
- जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की विविधता से है। इसमें पशु, पक्षी, पेड़-पौधे, कीट, सूक्ष्म जीव और समुद्री जीव शामिल हैं।
- सामान्य रूप से जैव विविधता को तीन भागों में बांटा जाता है; आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता।

Daily Current Affairs

Date : 23 May, 2026



- UNGA ने वर्ष 2011-2020 को जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में नामित किया था।
- वर्ष 2021-2030 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत् विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक' (Decade of Ocean Science for Sustainable Development) और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (UN Decade on Ecosystem Restoration) के रूप में घोषित किया गया।

जैव विविधता और सतत विकास लक्ष्य:

1. **SDG-2: शून्य भूख** - फसलों, पशुधन और पारिस्थितिक तंत्रों में जैव विविधता लचीली खाद्य प्रणालियों और दीर्घकालिक पोषण सुरक्षा का समर्थन करती है।
2. **SDG-3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण** - स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र औषधीय संसाधन प्रदान करते हैं और पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के संचरण के जोखिम को कम करते हैं।
3. **SDG-6: स्वच्छ जल और स्वच्छता** - वन, आर्द्रभूमि और स्वस्थ मिट्टी जल निस्पंदन, भंडारण और गुणवत्ता विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4. **SDG-13: जलवायु कार्रवाई** - जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जलवायु प्रणालियों को विनियमित करते हैं और चरम मौसम की घटनाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाते हैं।
5. **SDG-14: जल के नीचे जीवन** - समुद्री जैव विविधता महासागर के स्वास्थ्य, मत्स्य पालन और तटीय आजीविका का समर्थन करती है।
6. **SDG-15: भूमि पर जीवन** - स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करने से पर्यावास की हानि, प्रजातियों के विलुप्त होने और भूमि क्षरण को रोका जा सकता है।
7. **SDG-17: लक्ष्यों के लिए साझेदारी** - जैव विविधता संरक्षण जैविक विविधता पर सम्मेलन जैसे ढाँचों के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करता है।

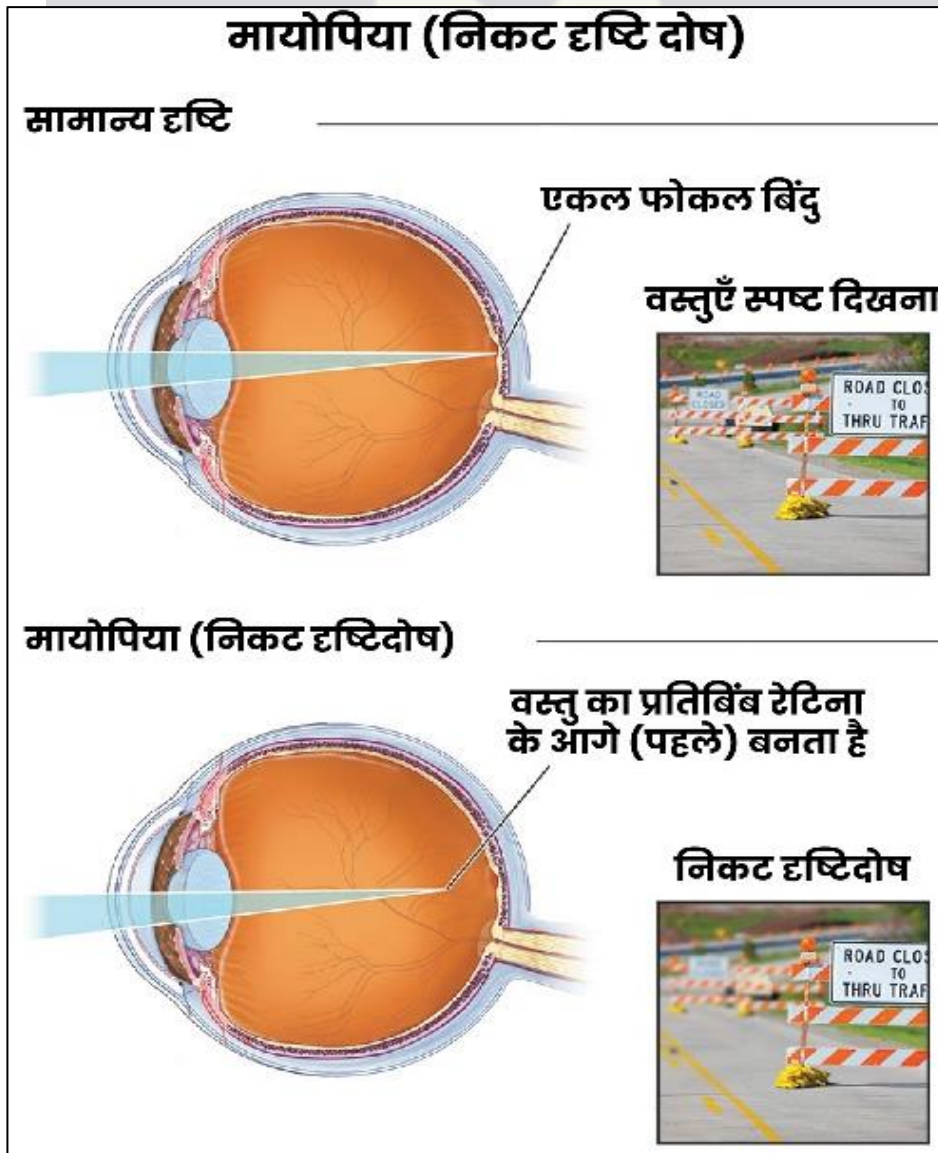
--:30:--

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚠

निकट दृष्टि दोष (मायोपिया)

📢 चर्चा में क्यों?

- निकट दृष्टि दोष (मायोपिया) तेजी से बढ़ता वैश्विक स्वास्थ्य विकार बनता जा रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक विश्व की लगभग आधी आबादी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो सकती है।



मुख्य बिन्दु:

मायोपिया

- **परिभाषा:** मायोपिया (निकट दृष्टि दोष) एक सामान्य अपवर्तक नेत्र विकार है जिसमें पास की वस्तुएँ तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएँ धुंधली दिखाई देती हैं।
- हाइपरोपिया (दूर दृष्टि दोष) में, पास की वस्तुएँ धुंधली दिखाई देती हैं क्योंकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय उसके पीछे बनता है।
- यह तब होता है जब नेत्रगोलक आगे से पीछे की ओर बहुत लंबा हो जाता है या कॉर्निया बहुत अधिक घुमावदार होती है।
- इस असामान्य आकार के कारण आने वाले प्रकाश की किरणें सीधे रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय उसके सामने केंद्रित होती हैं अर्थात् वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दूर की दृष्टि धुंधली हो जाती है।

बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-1'

(स्रोत: PIB और DD-NEWS)

चर्चा में क्यों?

- 22 मई, 2026 को ओडिशा के चाँदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से लघु दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-वन का रणनीतिक बल कमान के तत्वावधान में सफल परीक्षण किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- अग्नि-वन लघु दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली और स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे त्वरित तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है।
- एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का परीक्षण:** इससे पूर्व 8 मई, 2026 को भारत ने अत्याधुनिक एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का ओडिशा स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री-एंट्री व्हीकल तकनीक (MIRV) का उपयोग किया गया था।